समाजवादी पार्टी

सत्ताइस का संकल्प

पीडीए का प्रणपत्र



संकल्प पत्र के प्रमुख वादे

जन-मन का मैनिफेस्टो • 2027

/samajwadiparty

www.samajwadiparty.in

PREAMBLE : PDA KA PRANPATRA

उद्देशिका : पीडीए का प्रणपत्र

हम, 'पीडीए के लोग',उत्तर प्रदेश को एक सम्पूर्ण सुख-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित व 'प्रेम, दया, अपनापन' के सौहार्दपूर्ण गुणों से परिपूर्ण एक समावेशी और सकारात्मक राज्य बनाने के लिए दृढ़संकल्पित होकर:

अपने समस्त प्रदेशवासियों की ख़ुशहाली और तरक़्क़ी के लिए;

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बिना किसी भेदभाव के सबके लिए बराबरी से सुनिश्चित करने हेतु 'सामाजिक न्याय का राज' लाने के लिए;

अपने हर हक़-अधिकार की हिफ़ाज़त करने वाले व जुल्म और सितम की नाइंसाफ़ी मिटाकर, सबको सार्वजनिक जीवन व नौकरी आदि हर क्षेत्र में सम्मानसहित आगे बढ़ने के लिए बराबर अवसर देनेवाले 'संविधान और आरक्षण' की रक्षा के लिए;

हर 'पीड़ित, दुखी, अपमानित' व शोषित, वंचित और ग़रीब की व्यक्तिगत गरिमा, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना के लिए;

हर ज़रूरतमंद बीमार, रोगी, अस्वस्थ नागरिक, गर्भवती, जच्चा-बच्चा, बुज़ुर्ग-वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, निःशुल्क स्वास्थ्य-चिकित्सा सेवा व कारगर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए;

महिलाओं को सशक्त, सबल, आत्मनिर्भर बनाने तथा हर स्त्री के मान-सम्मान, सुरक्षा, निशुल्क शिक्षा, और समान अवसर व सबलीकरण के लिए;

किसानों की मेहनत को सम्मानजनक लाभकारी मूल्य, समय पर भुगतान व मजदूरों को मेहनत का सही मूल्य दिलवाने व सबके जीवन स्तर को सुधारने के लिए;

युवाओं-अभ्यर्थियों के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में निष्पक्ष नौकरी-रोज़गार, प्रतीक्षा-सूचीकरण, छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण, विदेशी शिक्षा, खेल व कला आदि रुचिकर क्रिएटिव फ़ील्ड में प्रशिक्षण-आर्थिक मदद और स्टार्ट-अप के अवसरों को बढ़ाने के लिए;

फेरी-पटरी-रेहड़ीवालों से लेकर छोटे व बड़े दुकानदारों, कारोबारियों, व्यापारियों, कल-कारखाना संचालकों व उद्यमियों-उद्योगों के लिए सरल-सुरक्षित व्यापारिक संरचना, बिजनेस फ्रेंडली फ़ास्ट- ट्रैक सिंगल विंडो पॉलिसी, चतुर्दिक सुरक्षा, सुरक्षित-त्वरित बीमित परिवहन-यातायात सेवा, वित्त-निवेश के लिए प्रोत्साहनकारी नीति बनाने व 'कंपनियों से कमीशनख़ोरी' करके महंगाई बढ़ाने की भ्रष्ट नीति को प्रतिबंधित करके व 'दाम बाँधो' के माध्यम से मुनाफ़ाख़ोरी रोककर बेतहाशा महंगाई से राहत दिलाने के लिए;

शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के गौरव को पुनर्स्थापित करने, बंद किए गए प्राथमिक विद्यालयों को फिर से शुरू करने, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और हर स्तर के शिक्षकों के लिए सम्मानजनक वेतन, स्थायी नौकरी और शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था को नियमित, पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए।

आशा, आंगनबाड़ी, सहायिका, नर्सिंग स्टाफ, संविदाकर्मी, आउटसोर्सिंग और चतुर्थ श्रेणी सहित अन्य सभी सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारियों व नौकरीपेशा-पेशेवर, दैनिककर्मियों के लिए सम्मानजनक वेतन, समायोजन, सामाजिक सुरक्षा, न्यायसंगत सेवा शर्तें तथा पुरानी पेंशन लागू करने के लिए;

क़ानून-व्यवस्था को आधुनिक एआई तकनीक, बॉडी-कैम, सीसीटीवी नेटवर्क, फोरेंसिक लैब और डेटा-आधारित पुलिसिंग से सुसज्जित करने व पुलिस व्यवस्था को राजनीतिक दबाव, जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार और हिरासत में हिंसा से पूर्णतः मुक्त कर न्यायसंगत बनाने, महिला सुरक्षा के लिए 1090 व डायल-112 को और अधिक सशक्त, त्वरित और जवाबदेह बनाने, फ़ास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने तथा हर नागरिक के लिए 'क़ानून का राज व भयमुक्त समाज' स्थापित करने के लिए;

सड़क, पुल, रेल, बस, हवाई संपर्क, हाईवे, मेट्रो, रोपवे, आधुनिक मंडी, सस्ती बिजली व पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं को हर गांव, बस्ती और शहर तक समान रूप से पहुँचाने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास तथा बिजली, पानी, सीवर, सड़क, वाईफाई, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट आदि से सुसज्जित पूरी तरह से नये गाँव बनाने-बसाने के लिए;

कलाकारों, अभिनेताओं, रंगकर्मियों, गायकों, चित्रकारों, खिलाड़ियों, शिल्पकारों, बुनकरों, कारीगरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, डॉक्टरों, सीए, अधिवक्ताओं, समाजसेवियों, पत्रकारों, फ़िटनेस एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर व अन्य किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सामाजिक योगदान देनेवालों की सुविधा व सम्मान हेतु योजनाएं बनाने व 'यश भारती सम्मान' को अधिक राशि के साथ पुनः शुरू करने के लिए;

उत्तर प्रदेश में आपसी भाईचारा, गंगा-जमुनी तहजीब और राष्ट्र की एकता-अखंडता को सुदृढ़ करने वाले समन्वयकारी, सहनशील भाव-विचार से संपन्न सौहार्दपूर्ण 'बंधु-राष्ट्र' के निर्माण के लिए;

और कुल मिलाकर नये युग की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं व न्यू जेनरेशन की आधुनिक आकांक्षाओं को आत्मसात् करते हुए, 'NEO INDIA' बनाने के लिए 'जन-मन मैनिफेस्टो 2027' के रूप में 'पीडीए का प्रणपत्र' आज दिनांक 26 नवम्बर, 2026 को जारी करते हुए, इसे अपनी दृढ़ वचनबद्धता से संकल्पित करते हैं।

डॉ. राममनोहर लोहिया

- “भारत की असमानता केवल आर्थिक नहीं है; यह सामाजिक भी है।”
- “भारत में मेरे जीवन का उद्देश्य सभी के लिए समानता, लोकतंत्र, युक्तिवाद, अहिंसा और समाजवाद है।”
- “महिलाओं के लिए समानता केवल समान अधिकारों की मांग नहीं करती, बल्कि विशेष अवसरों की भी मांग करती है।”
- “गरीबी पर युद्ध केवल दिखावा है, जब तक कि उसके साथ ही इन दोनों प्रकार के भेदभावों के विरुद्ध एक सचेत और निरंतर संघर्ष न हो।”

जयप्रकाश नारायण

- “सच्ची राजनीति मानव के सुख को बढ़ावा देने से संबंधित है।”
- “मेरा उद्देश्य सत्ता पर अधिकार करना नहीं, बल्कि जनता द्वारा सत्ता पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है।”

डॉ. बी. आर. अंबेडकर

- ·“मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस स्तर से मापता हूँ, जिस स्तर तक उसमें महिलाओं ने प्रगति प्राप्त की है।”

सेवा में निहित ... सर्व समाज का हित

ताकि हक़ से आगे बढ़ सके हर कमज़ोर, ग़रीब दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित

“समाजवादी पार्टी एक दल नहीं है,समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आँधी है, समाजवादी पार्टी एक सैलाब है।"

- समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है।
- समाजवादी पार्टी एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे।
- जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जिसे कभी किसी के आगे सर न झुकाना पड़े ।



समाजवादी पार्टी की भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है। महात्मा गांधी, डॉ. लोहिया एवं डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखती है।

समाजवादी पार्टी का विश्वास ऐसी राजव्यवस्था में है, जिसमे आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण निश्चित रूप से हो।

पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय पर आधारित विशेष अवसर के सिद्धांत में समाजवादी पार्टी का विश्वास है।



PDA समाजवादी विचारधारा

हमारी पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है इसके जरिए हम सभी के लिए अवसर की समानता एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम एक ऐसा नीतिगत वातावरण बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव के समृद्ध हों। हम महिलाओं और युवाओं के विकास के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध हैं। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां गरीबी और भुखमरी को मिटाई जा सके और सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की असमानताओं को कम किया जा सके।हम राज्य को आर्थिक विकास के सतत पथ पर ले जाना चाहते हैं। हम लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। सुशासन हमारा आदर्श वाक्य है, समाजवादी पार्टी मानव संसाधन के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देती है। हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि किसान देश के प्रत्येक नागरिक का पेट भरते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, हम किसानों के जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने और प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि लाने के लिए उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां सार्वजनिक सेवाओं को प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचाया जाय और सभी की भागीदारी के माध्यम से एक जीवंत और ऊर्जावान वातावरण तैयार किया जा सके। जिससे समाज के सभी वर्गों में तरक्की और खुशहाली आ सके।

लोकतंत्र का सार यह नहीं है कि बहुमत शासन करेगा,
बल्कि यह है कि प्रत्येक नागरिक की बात सुनी जाएगी।

- डॉ. राममनोहर लोहिया



संवैधानिक अधिकार

- संविधान बचाने का अधिकार
- लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार
- मीडिया की आजादी का अधिकार
- लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता व स्वायत्तता का अधिकार
- न्याय और समानता का अधिकार



समाजवाद धन के वितरण के बारे में नहीं, शक्ति के वितरण के बारे में है।

- डॉ. राममनोहर लोहिया

सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार

- सामाजिक न्याय का अधिकार
- रोटी का अधिकार
- महंगाई से निजात पाने का अधिकार
- गरीबी से बाहर निकलने का अधिकार
- महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा और समान अवसर का अधिकार
- युवाओं को नौकरी और रोजगार का अधिकार
- युवाओं को पेपर लीक से मुक्त पारदर्शी एवं स्वच्छ परीक्षा व्यवस्था का अधिकार
- युवाओं को उत्तकृष्ठ गुणवत्ता की शिक्षा का अधिकार
- पिछडे, दलित, अल्पसंख्यक, महिलायें एवं गरीबों को शोषण से मुक्ति का अधिकार
- किसान को कर्ज मुक्त होने का अधिकार
- सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार
- आवारा पशुओं से खेत एवं जान को बचाने का अधिकार
- जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार
- गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार

- 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार
- गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार
- बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार
- बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार
- खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार
- सुविधा से FIR दर्ज होने का अधिकार
- किसान को अपनी उपज का MSP मिलने का अधिकार
- मजदूर को बेहतर जीवन का अधिकार
- उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं का अधिकार
- शहरों को कूडा मुक्त एवं स्वच्छ पेयजल का अधिकार

प्रणपत्र सूची

विषय	पृष्ठ
1. युवा एवं रोजगार	12
2. शिक्षा	14
3. सामाजिक न्याय	15
4. कृषि और ग्रामीण विकास	17
5. महिला-केंद्रित विकास	18
5. स्वास्थ्य	19
6. कानून व्यवस्था	20
7. सूक्ष्य लघु एवं मध्यम लघु उद्योग	21
8. समाजवादी डिजिटल पॉलिसी	22
9. व्यापार एवं वाणिज्य	22
10. श्रमिक सशक्तिकरण	22
11. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर	23
12. शहरी विकास	23
13. जल पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण	24
14. पर्यटन एवं संस्कृति	24
15. गवर्नेंस	25
16. महंगाई पर नियंत्रण	25
17. रक्षा बल	26
18. अल्पसंख्यक कल्याण	26
19. खेल	27
20. अधिवक्ता	27
21. मीडिया	27

युवा एवं रोजगार

1 समाजवादी पार्टी उ0प्र0 के युवाओं एवं युवतियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करेगी। इसके लिए सभी को-

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर सबको प्रदान किया जायेगा। विशेष तौर पर **PDA के छात्र और गरीब युवा को उच्च गुणवत्ता की समान शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।** इसके लिए विशेष राज्य शिक्षा नीति लायी जायेगी।

सभी पात्र युवाओं को सुरक्षित नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य के लिए व्यापक तौर के कौशल विकास केंद्र विकसित किये जायेगें। प्रति **वर्ष 5 लाख युवाओं को इन केंद्रों से लाभान्वित किया जायेगा।**

2. **सभी सरकारी पदों में समयबद्ध तरीके से रिक्तियां भरना पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जायेगा।**

3. हम ऐसी **भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली** विकसित करेंगे कि **पेपर लीक** की समस्या ही उत्पन्न न होने पाये और इसके लिए संबंधित अधिकारी और मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4 **सरकारी रिक्तियों का वार्षिक कैलेंडर बनाया जायेगा और सभी परीक्षायें समय पर आयोजित की जायेगीं।** जिन रिक्तियों के लिए एक परीक्षा देनी होगी उसे 3 माह में प्रक्रिया पूरी की जायेगी और जिनकी एक से ज्यादा परीक्षायें देनी होती है उन्हें 6 माह में पूरा किया जायेगा। परिणाम भी समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ घोषित किया जायेगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता को टॉलरेट नहीं किया जायेगा।

5 **हम प्रत्येक ग्रेजुएट छात्र को रोजगार अथवा नौकरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।** इसके लिए विशेष तौर से नौकरी से जुडे कौशल विकास की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। हम जब तक ग्रेजुएट को नौकरी अथवा रोजगार नहीं दिला पाते हैं तब तक उनको **प्रति माह 5 हजार रू0 का पोषण भत्ता** देना सुनिश्चित करेंगे।

6 **MSME** सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहित करके हम इसे विकास का इंजन बनायेंगे जिससे **2032 तक 1 करोड के ऊपर नौकरियां** इस क्षेत्र में सुनिश्चित हो पायें।

7 हमारा संकल्प है कि हम **5 सालों में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी** और **2 से 3 करोड़ युवाओं को रोजगार** अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध करायेंगे।

8 **स्मार्ट किसान सहायक योजना के तहत 5 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाया जायेगा** जिससे कृषि का आधुनिकीकरण हो सके ।

9 **AI (Artificial Intelligence)** के कारण जिन लोगों की नौकरिया चली गयीं है या जाने की संभावना है उन्हें चिन्हित कर उनका **कौशल विकास** किया जायेगा जिससे उनको रोजगार पाने में मदद मिल सके ।

10 **हमारा मत अग्निवीर की नीति के विरुद्ध है** । जब तक नीति में बदलाव नहीं होता है तब तक अग्निवीर जो स्थायी कमीशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं उन्हें **राज्य के पुलिस में एवं अन्य विभागों में रोजगार उपलब्ध** कराया जायेगा ।

11 छात्रों विशेषकर **बालिकाओं के लिए तहसील स्तर पर कौशल विकास और कैरियर परामर्श केंद्र बनाये जायेगे** और इसके द्वारा हर साल 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जायेगा ।

12 बड़े शहरों में **छात्रों एवं छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास** बनाये जायेगें ।

१३ शहरों के युवकों को रोजगार के लिए शहरी **रोजगार गारंटी** अधिनियम लाया जायेगा ।

शिक्षा

1. **समाजवादी पार्टी राज्य शिक्षा नीति** लायेगी जिससे सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर प्रदान हो पाये।
2. **वर्तमान सरकार द्वारा बंद किये गये 26 हजार प्राथमिक विद्यालयों को पुनः संचालित किया जायेगा** और उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
3. बड़े शहरों में **छात्रों एवं छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास** बनाये जायेगें।
4. बारहवीं कक्षा पास **छात्रों एवं छात्राओं के** लिए **लैपटॉप वितरण योजना पुनः लागू** की जायेगी।
5. **सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा दी जायेगी।**
6. **शिक्षा में GSDP का 6 प्रतिशत धनराशि व्यय** करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक उत्कृष्ट **गुणवत्ता की शिक्षा की व्यवस्था** सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
8. उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जायेगा जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके और **शिक्षा और रोजगार में कोई मिसमैच न होने पाये**।
9. **राज्य की शिक्षा प्रणाली में सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ एक साल के भीतर प्रभावी की जायेगी** और **अनुबंध** नियुक्तियां बंद की जायेगी।
10. **शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए विधिक सलाह के अनुसार विशेष अभियान चलाया जायेगा।** जब तक यह न हो जाये तब तक के लिए उनके **मानदेय में रु० 5 हजार प्रति माह की वृद्धि** सुनिश्चित की जायेगी।
11. Unaided स्कूलों के लिए सरकार द्वारा **रु० 5 हजार विशेष मासिक अनुदान** दिया जायेगा।

सामाजिक न्याय

1. समाजवादी पार्टी का नारा **PDA के विकास** का है जिसका मतलब सभी पीडित, दुखी और अपमानित व्यक्तियों का **सम्मान देंगे** और उनका **सामाजिक और आर्थिक विकास** करेगें ।
2. हमारी सरकार **जातिगत जनगणना प्रदेश में शुरू** करेगी जिससे कि अलग-अलग जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी हो पाये और उसके अनुरूप उनके उत्थान की योजना विकसित की जा सकें ।
3. समाजवादी पार्टी की **सरकार दलितों, पिछडों, अल्पसंख्यक, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति** का पालन करेगी । किसी का भी अपमान और उत्पीड़न समाज में नहीं होने देगें ।
4. **निजी क्षेत्र के विद्यालयों में** आरक्षण देने वाले विद्यालयों में **आरक्षित विद्यार्थियों की फीस सरकार द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी** ये व्यवस्था **पिछड़े, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों पर लागू होगी** ।
5. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति** के लिए विशेष घटक योजना (Special Component Plan) के अनुसार **20% के बजट** उनके उत्थान के लिए व्यय की जायेगी ।
6. **पीडीए, महिलाओं और गरीबों** के लिए प्रदेश में भर **समाजवादी कैन्टीन** खोली जायेगी जिसमें **रु० 5 की थाली** उपलब्ध करायी जायेगी ।
7. **प्रवासीय मजदूरो** की खुशहाली पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और इसके लिए **प्रवासी मजदूर हेल्पलाइन** बनायी जायेगी ।
8. **बुजर्ग महिला कारीगरों को रु० 40 हजार सालाना पेंशन** दी जायेगी ।
9. **वरिष्ठ नागरिकों** की सुरक्षा एवं कल्याण सभी मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए **वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम (Senior Citizen Welfare Act)** लाया जायेगा । यह भी व्यवस्था की जायेगी वरिष्ठ नागरिक **डिमेंशिया** से पीड़ित न होने पाये और इस उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी सुविधा के लिए **वृद्धाश्रम (Old Age Home)** एवं **क्लब** बनाये जायेगें ।

10. **दिव्यांग** जनों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ ,रोजगार, शिक्षा एवं **सुगम्यता** की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । इनको **इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल (Electric Tricycle)** सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा ।
11. **सभी सरकारी ठेकों और लाभार्थी योजनाओं में गरीब एवं शोषित व्यक्तियों को उनकी आबादी अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ।**
12. **अनुसूचित जनजाति के लिए बोर्ड बनाया जायेगा ।**
13. **अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों** की स्वास्थ शिक्षा एवं अन्य समस्याओं हल करने के लिए और उनके **कल्याण के लिए बोर्ड** बनाया जायेगा ।
14. **मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दलित विकास परिषद का गठन** किया जायेगा जो दलितों का कल्याण सुनिश्चित करेगा ।
15. सरकारी सेवाओं मे **बैकलॉग पदों** को भरने के लिए **विशेष भर्ती अभियान** चलाया जायेगा ।
16. **आरक्षण** को प्रभावी रूप से **संविधान के अनुसार लागू** किया जायेगा ।
17. दलित उद्यमियों को बढावा देने के लिए **दलित स्टार्टअप फंड** बनाया जायेगा ।
18. **50 करोड़** तक के सरकारी ठेकों में दलित एवं पीडीए के लिए **50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित** किया जायेगा।

कृषि और ग्रामीण विकास

1. हम उत्तर प्रदेश में सभी **23 फसलों और दूध** के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की लीगल गारंटी** सुनिश्चित करेंगे जिससे कि सभी किसानों को MSP मिल सके ।
2. **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** के बाहर **आलू, टमाटर, प्याज एवं अन्य अधिसूचित फसलों** के लिए राज्य सरकार द्वारा **मूल्य क्षतिपूर्ति** व्यवस्था विकसित की जायेगी ।
3. ग्रामीण अर्थ व्यवस्था एवं बुनियादी ढांचे को बढावा देने के लिए **रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर** में **1.5 लाख करोड़** की **धनराशि की व्यवस्था** की जायेगी जिससे ग्रामों का विकास हो सके।
4. हम **किसानों के ऋण माफी (Loan waiver)** करने की योजना तत्कालिक प्रभाव से लागू करेगें ।
5. हम **15 हजार करोड़** का **कॉर्पस फंड** बनाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि **गन्ना किसान का भुगतान 24 घंटे में** हो जाये । गन्ना किसानों का मूल्य उनकी लागत की वास्तविक गणना करते हुए प्रति वर्ष बढ़ाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. **सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली** दी जायेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के **घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली** दी जायेगी ।
7. हम राज्य में **न्यू विलेज क्लस्टर** स्थापित करेंगे जिससे गांव में सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी तथा इंटरनेट से भी जोडा जायेगा और गांव का विकास नियोजित ढंग से सुनिश्चित किया जायेगा ।
8. हम **73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक पंचायत तथा जिला पंचायत** को सुदृढ बनायेंगे । प्रत्येक ग्राम, विकास खण्ड एवं जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनायी जायेगी और इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी ।

महिला-केंद्रित विकास

“स्त्री पुरुष की सहचरी है, जिसे समान मानसिक क्षमताएँ प्राप्त हैं। उसे पुरुष की गतिविधियों के सूक्ष्मतम विवरण में भाग लेने का अधिकार है, और उसे पुरुष के समान स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता का समान अधिकार प्राप्त है। जैसे पुरुष अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोच्च स्थान का अधिकारी है, वैसे ही स्त्री भी अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोच्च स्थान की अधिकारी है। यह स्थिति प्रकृति का स्वाभाविक नियम होना चाहिए, न कि केवल पढ़ने-लिखना सीखने का परिणाम। दुष्ट प्रथाओं के बल पर, यहाँ तक कि सबसे अज्ञानी और निकृष्ट पुरुषों ने भी स्त्रियों पर वह श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है, जिसके वे हकदार नहीं हैं और जो उन्हें प्राप्त नहीं होनी चाहिए। हमारे अनेक आंदोलन अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हमारी स्त्रियों की स्थिति ऐसी है।”

— महात्मा गांधी, भगिनी समाज, बंबई, 20 फरवरी 1918

"महिलाओं के लिए समानता केवल समान अधिकारों की मांग नहीं करती, बल्कि विशेष अवसरों की भी मांग करती है।”

— डॉ. राम मनोहर लोहिया

"महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता है।"

— मुलायम सिंह यादव

महिला सशक्तिकरण हेतु विस्तृत घोषणापत्र जल्द ही आपके समक्ष होगा...
Detailed Women’s Manifesto to follow soon...

स्वास्थ्य

1. **राज्य स्वास्थ्य नीति 2027** लायी जायेगी जो चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को उत्कृष्टता का स्तर प्रदान करायेगी और सभी नागरिकों को **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा किफ़ायती दरों पर उपलब्ध करायी जायेगी** । सरकारी अस्पतालों में पीडीए और **गरीब नागरिकों को मुफ्त इलाज** सुनिश्चित कराये जायेगा ।
2. सभी **जिला अस्पतालों** का उच्चीकरण किया जायेगा और उन्हें **सेंटर आफ एक्सीलेंस** बनाया जायेगा । **सभी जिला अस्पतालों को आईसीयू वेंटीलेटर की व्यवस्था** सुनिश्चित करायी जायेगी । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सीएचसी का भी सुदृढीकरण सुनिश्चित किया जायेगा ।
3. सभी **18 मंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल** स्थापित किये जायेगें ।
4. **108, 102 एम्बुलेंस नेटवर्क** को उन्नत लाइव सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनर्जीवित और सुदृढ किया जायेगा ।
5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों को **10 लाख रु० का हेल्थ इंश्योरेंस** उपलब्ध कराया जायेगा ।
6. सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें सस्ते दर पर उपलब्ध कराना हमारी सरकार सुनिश्चित करायेगी ।
7. लखनऊ में **अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी कैंसर उपचार अस्पताल** जो समाजवादी सरकार ने बनाया था जो अभी क्रियाशील नहीं किया गया है, को उत्तर भारत के सबसे उत्कृष्ठ कैंसर अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा और यहाँ कैंसर का मुफ्त इलाज होगा । उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अब इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पडेगा ।
8. समाजवादी सरकार द्वारा **स्टेट न्यूट्रेशन मिशन** शुरू किया गया था उसके और सुदृढ करके प्रदेश में **कुपोषण (Malnutrition)** की समस्या को समाप्त किया जायेगा ।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में **5 सुपर स्पेसलिटी अस्पताल** स्थापित किये जायेगें ।
10. प्रदेश मे सभी **डाक्टर एवं नर्स एवं पैरामिडिक्स की रिक्तियों को तत्काल प्रभाव से भरा जायेगा** ।
11. प्रदेश में **जन स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर (Public Health Management Cadre)** बनाया जायेगा ।

कानून व्यवस्था

1. **पीडीए सरकार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध** सख्त रुख अपनायेगी और इसके प्रति **जीरो टालरेंस** की नीति का पालन करेगी।
2. समाजवादी पार्टी की सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक विशेषकर महिलाओं, पिछडो, दलितों एवं अल्पसंख्यकों के प्रति संगठित अपराध और हेट **क्राइम के खिलाफ भी जीरो टालरेंस** की नीति का पालन करेगी।
3. **पीडीए सरकार किसी भी प्रकार का दंगा जाति एवं धर्म के आधार पर नहीं होने देगी** और उसके लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी।
4. **महिलाओं और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध** जो निरंतर बढ रहे है उनके विरुद्ध **विशेष सतर्कतापूर्वक कार्यवाही** कर नियंत्रित करेगी।
5. **साइवर क्राइम कंट्रोल के लिए सभी जिले में साइवर यूनिट** स्थापित किये जायेगें। साइवर क्राइम को पूर्णरूप से नियंत्रित किया जायेगा।
6. सभी प्रमुख शहरों में **ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक सुधार AI युक्त टेक्नोलॉजी** से कराया जायेगा।
7. **किसी भी माफिया या प्रभावशाली व्यक्तियों को किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जायेगा इसके लिए एक विशेष STF बनायी जायेगी जो जमीनी विवादों को हल करने के लिए कार्यवाही करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति किसी भी गरीब पिछडे और दलित एवं असहाय व्यक्ति की भूमि पर कब्जा न करने पाये। इसके लिए डायल 100 /112 की तरह अलग रंग की गाड़ियां बनायी जायेगी जो निरंतर पेट्रोलिंग कर इस पर नियंत्रण सुनिश्चित करेंगी।**
8. प्रदेश भर में किसी भी **माफिया एवं गुंडों को पनपने नहीं दिया जायेगा** और उनके विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
9. **व्यापारी, दुकानदार, तथा उद्यमियों को कोई भी माफिया अथवा बाहुबली परेशान नहीं कर पायेगा** और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं कर पायेगा इसके लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी **प्रमुख बाजारों में डायल 100/112 की गाड़ियां तैनात की जायेगी** और जिले के संबंधित अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।
10. महिला की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है इसके लिए डीजीपी के नियंत्रण में **विशेष महिला पुलिस का ढांचा** बनाया जायेगा जो गांव तक अपनी पहुंच रखेगा और **महिलाओं के प्रति अपराध को रोकेगा** और अपराध होने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करेगा।

11. एक वर्ष के भीतर गांव और कस्बों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर **सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन निगरानी** व्यवस्था स्थापित की जायेगी। इस व्यवस्था को **यूपी 100/112 के नियंत्रण केंद्रो से जोड़ा जायेगा।**

12. अपराध नियंत्रण के हर पहलू पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए **AI आधारित व्यवस्था** व्यापक रूप से लागू की जायेगी।

13. **यूपी पुलिस से सभी खाली पदों** को **तत्काल भरा जायेगा** और **महिलाओं को नयी रिक्तियों में 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** किया जायेगा।

14. पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएंगे **पुलिस के काम के घंटे सुनिश्चित किये जाएंगे** और **साप्ताहिक छुट्टी का प्राविधान होगा** एवं **वर्क लाइफ बैलेंस** का प्राविधान होगा। **पुलिस कर्मियों को पड़ोसी जिलो में तैनाती का अवसर** दिया जायेगा और **प्रमोशन के अवसर** दिया जायेगे। सभी पुलिस कर्मियों के लिए **सरकारी आवास की व्यवस्था** सुनिश्चित करायी जायेगी।

15. **पुलिस कर्मियों को साइकिल के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता तथा मोबाइल भत्ता** दिया जायेगा। **पति-पत्नी दोनों के पुलिस विभाग में होनें पर उनकी पोस्टिंग एक ही जिले में** करने का यथासंभव प्रयास किया जायेगा। **पुलिस कर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ता** में वृद्धि की जायेगी।

16. **1090 की व्यवस्था को पुनः सुदृढ** करके महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

17. **डायल 100/112 की व्यवस्था को सुदृढ** किया जायेगा जिससे कम से कम समय में पुलिस बल मौके पर पहुंचेगा एवं नागरिकों एवं विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करेगा।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम लघु उद्योग

1. पीडीए सरकार राज्य में **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम लघु उद्योग (MSME) सेक्टर** को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी और उन्हें विकास के इंजन के रूप में बदलेगी।

2. **टाइम बाउंड सिंगल विंडो** और **सिंगल रूफ क्लीरियंस** की वास्तविकता सुनिश्चित करेगी।

3. **नयी औद्यौगिक नीति 2027** लायी जायेगी जिससे उ0प्र0 में औद्यौगीकरण सुनिश्चित हो सके।

4. नयी औद्यौगिक नीति में **रोजगार सृजन** को बढ़ावा दिया जायेगा

5. **औद्यौगिक क्षेत्र की भूमि को फ्री होल्ड किया जायेगा।**

6. **स्टार्टअप को बढ़ावा** देने की विशेष योजना लायी जायेगी और स्टार्ट अप का ईको सिस्टम पूरे प्रदेश में विकसित किया जायेगा।

समाजवादी डिजिटल पॉलिसी

1. यूपी के **प्रमुख शहरों को AI और IT हब** के रूप में विकसित किया जायेगा ।
2. सभी **गाँवों और शहरों में वाईफाई (WIFI) जोन** विकसित किये जायेगें ।
3. **शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति व्यवस्था, कृषि उद्योग एवं प्रशासन एवं अन्य सभी क्षेत्रो में AI** का व्यापक प्रयोग करके और प्रभावी, उपयोगी एवं लाभदायक बनाया जायेगा।
4. **उत्तर प्रदेश को पूरे देश में AI के क्षेत्र में सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प** पीडीए सरकार का रहेगा ।

व्यापार एवं वाणिज्य

1 **व्यापार सुरक्षा आयोग का गठन किया जायेगा,** हर हाल में व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी ।
2. **व्यापारियों की सुरक्षा** के लिए विशेष पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी जो **100/112 की तरह गाड़ियों को सभी प्रमुख बाजारों में तैनात** करेगा जिससे वहाँ किसी भी प्रकार का अपराध या उत्पीड़न की कार्यवाही न होने पाये ।

श्रमिक सशक्तिकरण

1. **डायल 1890 मजदूर पावर लाइन** की स्थापना की जायेगी जो प्रदेश और प्रदेश के बाहर मजदूरों की समस्या के निदान के लिए कार्य करेगी ।
2. **प्रवासी मजूदर कार्ड योजना** शुरू की जायेगी जो मजदूरों की विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करायेगी ।
3. समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए संवैधानिक अधिकार बनाया जायेगा ।
4. रु० 5 में **समाजवादी थाली** की व्यवस्था श्रमिकों के लिए की जायेगी ।
5. निर्माण श्रमिकों में **वृद्ध महिला एवं पुरूषों को रु०40 हजार** की पेंशन दी जायेगी और रु० 10 लाख का स्वास्थ बीमा दिया जायेगा।

पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

1. **सभी तहसील मुख्यालयों को 4 लेन नेटवर्क से जोड़ा जायेगा ।**
2. सभी **गावों को पक्की सड़को से जोड़ा जायेगा** और गांव के अंदर की सड़को को आरसीसी से बनाया जायेगा ।
3. राज्य भर में **प्रत्येक गांव में 24 घंटे** और अन्य **कस्बे एवं शहरों में भी 24 घंटे बिजली पूर्ति सुनिश्चित** की जायेगी ।

शहरी विकास

1. 10 लाख के ऊपर आबादी के **प्रमुख शहरों में 24 X 7 जल आपूर्ति** सुनिश्चित करायी जायेगी ।
2. सभी शहरों में **जल जमाव एवं बाढ एवं जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज का प्लान** बनाया जायेगा और प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा ।
3. सभी **शहरों में ट्रैफिक की व्यवस्था पूर्णरूप से सुनिश्चित** की जायेगी ।
4. **प्रदेश में नयी ग्रीन फील्ड आधुनिक टाउनशिप** विकसित की जायेगी ।
5. शहरों को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए विशिष्ट योजना बनाकर प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा और **वायु प्रदूषण से नागरिकों को मुक्ति** दिलायी जायेगी ।
6. सभी **प्रमुख शहरों के कूड़ा मुक्त किया जायेगा** और इसके लिए **आधुनिक सॉलिड वेस्ट सिस्टम मैनेजमेंट** लागू किया जायेगा ।
7. **सभी शहरों में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की योजना पुनः लागू की जायेगी ।**
8. अंतराष्ट्रीय मानको के अनुसार **रिवर फ्रंट** विकसित किये जायेगे ।

जल पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण

1. **उ०प्र० की प्रमुख नदियों को साफ करने का अभियान** चलाया जायेगा जिससे सभी नदी स्वच्छ और निर्मल की जा सके।
2. संपूर्ण यूपी में **साइकिल हाईवे नेटवर्क** की स्थापना की जायेगी।
3. **इलेक्ट्रिक वाहन** खरीदने के लिए **उपभोक्ताओं को प्रत्साहित करने की योजना** लायी जायेगी।
4. प्रदेश में **ईको टूरिज्म** को बढावा दिया जायेगा और **स्टेट वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टिट्यूट** की स्थापना की जायेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति

1. **पर्यटन विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया जायेगा** क्योंकि इससे व्यापक रोजगार की संभावना उपलब्ध हो जायेगी।
2. **हास्पिटैलिटी एंड टूरिज्म प्रशिक्षण संस्थान** स्थापित किये जायेगें।
3. प्रदेश के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध शहरों को **हेरिटेज आर्क (Heritage Arc)** के रूप में प्रभावी रूप से विकसित किया जायेगा।

गवर्नेंस

1. **भ्रष्टाचार नियंत्रण में तकनीकी का प्रयोग कर व्यापक कार्यवाही की जायेगी ।** किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।
2. 73वें औव 74वें संविधान संशोधन को उसकी वास्तविक मनशा के अनुसार लागू किया जायेगा । **ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को Funds (निधि), Functions (कार्य), और Functionaries (कार्मिक / पदाधिकारी) से सुदृढ** किया जायेगा ।
3. **2005 से पूर्व की पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जायेगा ।**
4. **आउटसोर्सिंग (Outsourcing)** की व्यवस्था समाप्त की जायेगी ।
5. **लोक सेवा वितरण अधिनियम (Public Service Delivery Act)** लाया जायेगा जिससे शासन व प्रशासन की आम नागरिक के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी और समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी ।
6. **Outcome Budgeting** की व्यवस्था लागू की जायेगी
7. **ई-ऑफिस की व्यवस्था** पूरे प्रदेश में लागू करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
8. सरकार की **सभी सुविधाओं को नागरिकों के घर (Door step) तक पहुंचाने की व्यवस्था** की जायेगी ।

महंगाई पर नियंत्रण

1. हमारा वादा है कि हम बढते हुए **दामों को नियंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे** इसके लिए माननीय लोहिया जी के परिकल्पना के अनुसार दाम बांधो की नीति लागू करेंगे । प्रमुख शहरों एवं कस्बों एवं ग्रामों में **दाम बांधो बाजार खोले जायेगें** जिससे सभी **आवश्यक वस्तुयें नियंत्रित दाम पर उपलब्ध हो पायें ।**
2. **लोहिया जी** के परिकल्पना के अनुसार **महंगाई** और निरंतर दाम बढोत्तरी से नागरिकों को **राहत** दिलाने के लिए इस **दाम बांधो योजना** के अंतर्गत हर आवश्यक वस्तु के दाम को नियंत्रित किया जायेगा ।
3. **स्कूल की फीस और अस्पताल के खर्चों को भी सीमित (Cap)** किया जायेगा ताकि आम लोग सस्ते दर पर अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सके और अस्पतालों में इलाज करा सकें । काला बाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्यवाही की जायेगी जिससे आवश्यक वस्तुयें नियमित मूल्य पर उपलब्ध हो सके ।

रक्षा बल

1. **राष्ट्रीय सीमा में तैनात सैनिको एंव अधिकारियों एवं उनके परिवार और उनकी जमीन की सुरक्षा** के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहेगी।
2. **शहीदों के लिए पेंशन** व्यवस्था शुरू की जायेगी और **उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा** दी जायेगी।
3. सैनिकों द्वारा संपत्ति खरीदने में **स्टैम्प ड्यूटी से छूट** दी जायेगी।
4. **समाजवादी पार्टी 'अग्निवीर योजना' का विरोध करती है** और मानती है कि इससे हमारे रक्षा बल (Defence Forces) कमजोर होंगे। हम इस व्यवस्था को बदलने का राष्ट्रीय सरकार से पूरा अनुरोध करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक जिन अग्निवीर को सेना में पर्मानेन्ट कमीशन नहीं मिलती है उन्हें **राज्य के पुलिस बल एवं अन्य पदों पर** नियुक्त कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

अल्पसंख्यक कल्याण

1. सभी अल्पसंख्यकों को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी और उनके विरुद्ध **घृणा अपराध (Hate Crime) की पूर्ण रूप से रोकथाम** सुनिश्चित की जायेगी।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुसार भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा।
3. **अल्पसंख्यक आय एवं कल्याण का गठन** किया जायेगा जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कारीगरों के लिए **लिविंग वेज स्कीम लागू** की जायेगी।
4. **कारीगर पेंशन रु० 40 हजार प्रति वर्ष** देना सुनिश्चित किया जाएगा।
5. कारीगरो के लिए बीमा मुआवजा की राशि **रु० 10 लाख** की जायेगी।
6. **बुनकरों को बिजली आपूर्ति पर सब्सिडी** दी जायेगी।
7. संविधान के अनुसार **अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं कल्याण** सुनिश्चित किया जायेगा।

खेल

1. प्रदेश में **तीन विश्वस्तरीय स्डेडियम** बनाये जायेगें ।
2. राज्य भर में **दस स्पोर्ट्स कालेज** बनाये जायेगें ।
3. उत्तर प्रदेश में फुटबाल, क्रिकेट, हाकी, कबड्डी, टेनिस बाल क्रिकेट एवं लोकप्रिय खेलों के लिए **विशेष स्पोर्ट्स लीग प्रारंभ की जायेगी** ।

अधिवक्ता

1. युवा अधिवक्ताओं को **वजीफा या आर्थिक सहायता** दी जायेगी ।
2. **अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम (Advocates Protection Act)** लागू किया जायेगा ।
3. अधिवक्ताओं के लिए **ग्रुप हाउसिंग** और **कैशलेस स्वास्थ बीमा योजनाए** उपलब्ध करायी जायेगी ।
4. सभी तहसीलों अदालतों में सरकार **चैंबर** उपलब्ध करायेगी और आवश्यक **धनराशि** भी देगी ।
5. **न्यायालयों** में **महिला अधिवक्ताओं** के **छोटे बच्चों के लिए देखभाल केंद्र** बनाये जायेगें ।

मीडिया

1. मीडिया कर्मियों और फील्ड लेवल के पत्रकारों के **कल्याण के लिए नीति लागू** की जायेगी जिसमें **स्वास्थ बीमा** और **सामाजिक सुरक्षा** शामिल होगी ।
2. स्थानीय मीडिया कर्मियों को **डिजिटल ढांचा** उपलब्ध कराने के लिए सभी तहसीलो में **मीडिया सुविधा केन्द्र** बनाया जायेगा ।
3. नोयडा और लखनऊ में **मीडिया कन्वेंशन सेंटर** बनाया जायेगा ।
4. **यूट्यूबरों एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (YouTube and Social Media Influencers)** के कल्याण के लिए **नीति बनाकर** उन्हें आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी ।


समाजवादी पार्टी
पीडीए का
प्रणपत्र
QR कोड स्कैन करें और
वाट्स-एप चैनल से जुड़ें
/Samajwadi Party
/samajwadiparty